

प्रेषक,

डी० सेंथिल पाण्डेयन,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,

उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद,

ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक)

देहरादून: दिनांक 09 मार्च, 2015

विषय:- भारत सरकार द्वारा किए गये संशोधनों के दृष्टिगत कस्तूरबा गौंधी आवासीय बालिका विद्यालयों में कार्यरत कर्मियों के मानदेय/सेवा शर्तों में संशोधन किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-534/के०जी०बी०वी०/2014-15 दिनांक 27-06-2014, पत्र संख्या-1614/के०जी०बी०वी०/2014-15 दिनांक 07-11-2014 एवं पत्र संख्या-1979/के०जी०बी०वी०/2014-15 दिनांक 12-01-2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि के०जी०बी०वी० छात्रावास में कार्यरत अल्पकालिक अध्यापिकाएं एवं अन्य कर्मियों के मानदेय इत्यादि में भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, नई दिल्ली के पत्र संख्या-F.No-2-16/2013-EE.8 दिनांक 24 मार्च, 2014 द्वारा किये गये संशोधनों के दृष्टिगत विभागीय प्रस्ताव के अनुक्रम में निम्नवत् संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(1)-अल्पकालिक शिक्षिकाओं को भारत सरकार के संशोधित मानकानुसार अर्थात् रु० 5000/- प्रतिमाह के स्थान पर रु० 7000/- प्रतिमाह का भुगतान किया जाय। अतिरिक्त भुगतान करने पर होने वाले व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(2)-के०जी०बी०वी० छात्रावास में कार्यरत संविदा कर्मियों (चौकीदार को छोड़कर) को वर्तमान में देय 10 माह के स्थान 11 माह का मानदेय भुगतान किया जाय।

(3)-लेखालिपिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर का पदनाम परिवर्तित करते हुए पूर्ण कालिक लेखाकार करते हुए उनको देय मानदेय रु० 7000.00 के स्थान पर रु० 10,000.00 प्रतिमाह किया जाय।

(4)-भारत सरकार द्वारा दो रसोइयों हेतु स्वीकृत मानदेय रु० 10,500.00 प्रतिमाह के अनुसार प्रति रसोइया रु० 5000.00 प्रतिमाह के स्थान पर प्रति रसोइया रु० 5250.00 प्रति माह दिया जाय।

(5)-वार्डन मद में प्रति वार्डन रु० 25000.00 की दर से भारत सरकार स्वीकृति प्राप्त होती है जबकि सभी वार्डन राजकीय अध्यापिका होने के कारण उनका वेतन राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अतः भारत सरकार से वार्डन हेतु स्वीकृत धनराशि राज्य सरकार के खाते में स्वतः समायोजित/जमा हो जायेगी।

...2/....

3- के0जी0बी0वी0 हेतु पूर्व में पद सृजन के शासनादेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें/दिशा निर्देश यथावत् लागू रहेंगे।

4- इन पदों पर होने वाला व्यय का वहन सर्व शिक्षा अभियान हेतु निर्धारित बजट अनुदान सँ0-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-अयोजनागत -01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-0104-सर्व शिक्षा अभियान (35 प्रतिशत राज्यांश)-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश भारत सरकार के पत्र दिनांक 24.03.2014 में निर्धारित तिथि अर्थात् 01.04.2014 से प्रभावी होगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सँ0-367(P)/XXVII(3)/2014-15 दिनांक 03-3-2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0 सैथिल पाण्डियन)  
सचिव।

संख्या-72 /XXIV(1)/2015-35/2004/तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- निदेशक, बेसिक/माध्यमिक, शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून।
- 5- समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- वित्त अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग।
- 7- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 8- बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, देहरादून।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)  
अनु सचिव